



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092020-222071  
CG-DL-E-28092020-222071

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/ आश्विन 6, 1942

No. 267]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

मामला सं. एडी(ओ आई)-28/2020

**विषय :** चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लूरोकार्बन्स (एचएफसी) कंपोनेंट आर-32 के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

**फा. सं. 6/33/2020-डीजीटीआर.**—1. मै. एसआरएफ लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से हाइड्रोफ्लूरोकार्बन्स (एचएफसी) कंपोनेंट आर-32, (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “पीयूसी” भी कहा गया है) पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

## **विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)**

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद “हाइड्रोफ्लूरोकार्बन्स (एचएफसी) कंपोनेंट आर-32” अथवा “डिफ्लूरोमीथेन” है। आर-32 अथवा डिफ्लूरोमीथेन का रासायनिक सूत्र सीएच<sub>2</sub>एफ<sub>2</sub> है और यह सीएस

नं. 75-10-5 में पंजीकृत है इसे एचएफसी-32, एफसी-32, फेरोन-32, मिथेलीन डिफ्लोराइड, मेथेलीन फ्लूओराइड, कार्बन फ्लूओराइड, हाइड्राइड, हालोकार्बन आर 32, फ्लूरोकार्बन आर 32 तथा यूएन 3252 के रूप में भी जाना जाता है। एच एफ सी कंपोनेंट आर-32 का प्रयोग मुख्यतः घरेलू एयर कंडीशनिंग प्रणाली में किया जाता है।

4. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 290339 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

#### **समान वस्तु**

5. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

#### **घरेलू उद्योग**

6. यह आवेदन एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वे न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में किसी आयातक से पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा आवेदक ने भारत में घरेलू समान उत्पाद के एकमात्र उत्पादक होने का दावा किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

#### **सामान्य मूल्य**

##### **चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

7. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को भारत में प्रदत्त या देय कीमत को विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य को भारत में प्रदत्त या देय कीमत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ जोड़ने के बाद विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर निर्धारित किया गया है।

#### **निर्यात कीमत**

8. संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय और वैट के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।
9. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन मार्जिन के न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक होने का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

#### **क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य**

10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन की दृष्टि से बड़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। यह भी दावा किया है कि कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण, और कीमत ह्रास के कारण उसका कार्य निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आवेदक ने दावा किया

है कि मात्रा और कीमत प्रभाव के जरिए उसके कार्य निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है जिससे मालसूची में वृद्धि हुई है और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट आई है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है।

### **पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

11. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

### **संबद्ध देश**

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

### **जांच की अवधि (पीओआई)**

13. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 - 31 मार्च, 2020 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2016 - 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल 2017- 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल 2018- 31 मार्च, 2019 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

### **प्रक्रिया**

14. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

15. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in) और [jd13-dgtr@gov.in](mailto:jd13-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
16. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातक और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
19. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

### **समय-सीमा**

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
23. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
25. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
29. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

30. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### **असहयोग**

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

वि. बि. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2020

**Case No. AD (OI)– 28/2020**

**Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Hydrofluorocarbons (HFC) component R-32 originated in or exported from China PR.**

**F. No. 6/33/2020-DGTR.**—1. M/s SRF Limited (hereinafter also referred to as the ‘Applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’) for imposition of Anti-dumping duty on Hydro Fluoro Carbon (HFC) Component R-32 (hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or ‘PUC’) from China PR (hereinafter referred to as the ‘subject country’).

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from the subject country and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods.

**Product Under Consideration**

3. The product under consideration in the present application is “Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 or Difluoromethane”. R-32 or Difluoromethane has the chemical formula CH<sub>2</sub>F<sub>2</sub> and is registered as CAS No. 75-10-5. It is also known as HFC-32, FC-32, Freon-32, Methylene difluoride, Methylene fluoride, Carbon fluoride hydride, halocarbon R32, fluorocarbon R32, and UN 3252. The HFC Component R-32 is mainly used in residential air conditioning systems.
4. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs sub-heading No. 290339. The customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

**Like Article**

5. The Applicant has submitted that there is no known difference in the subject goods produced by the Applicant and the one exported from the subject country. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject country in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

**Domestic Industry**

6. The application has been filed by SRF Limited. The Applicant has claimed that they are not related to an exporter or producer of the subject goods in the subject country or an importer in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules. Further, the Applicant has claimed to be the sole producer of the domestic like product in India. On the basis of information on record, it is noted that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

**Normal Value****Normal Value for China PR**

7. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value on the basis price payable in India, duly adjusted. The normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

**Export Price**

8. The export price for the subject country has been computed based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight and VAT.
9. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* show significant dumping margin above the *de minimis* in respect of the subject goods from the subject country. There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

**Injury and Causal Link**

10. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms, and also in relation to production in India. It has also been claimed that its performance has been adversely effected on account of price undercutting, price depression and price suppression. The Applicant has claimed that through the volume and price effect, its performance has been adversely impacted leading to an increase in inventories, and a decline in capacity utilization, market share, profits, return on capital employed and cash profits during the POI as compared to the preceding year. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject country.

**Initiation of Anti-Dumping Investigation**

11. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping in respect of the product under consideration originating and exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**Subject Country**

12. The subject country for the present investigation is China PR.

**Period of Investigation**

13. The period of investigation for the purpose of present investigation is from 1<sup>st</sup> April, 2019 to 31<sup>st</sup> March, 2020 (12 months). The injury investigation period will cover the periods, 1<sup>st</sup> April 2016- 31<sup>st</sup> March 2017, 1<sup>st</sup> April 2017- 31<sup>st</sup> March 2018, 1<sup>st</sup> April 2018- 31<sup>st</sup> March 2019 and the period of investigation.

**Procedure**

14. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

**Submission of Information**

15. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dir14-dgtr@gov.in](mailto:dir14-dgtr@gov.in) and [jd13-dgtr@gov.in](mailto:jd13-dgtr@gov.in).



16. The known producers/exporters in the subject countries, their Governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.
19. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

#### **Time Limit**

20. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

#### **Submission of Information on Confidential Basis**

22. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
23. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
24. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

30. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-Cooperation**

31. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority